

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
उच्चतर शिक्षा, शास्त्री भवन,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग-8 (तकनीकी)

देहरादून दिनांक 19 अगस्त, 2010

विषय:—एस्कार्ट फार्म, ग्राम कुण्डेश्वरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में सीलिंग में प्राप्त अतिरिक्त भूमि में से 200 एकड़ भूमि, भारतीय प्रबन्धक संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1869/XVIII(II)/2010-5(137)/2008 दिनांक 09.08.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय एस्कार्ट फार्म, ग्राम कुण्डेश्वरी, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में सीलिंग में प्राप्त अतिरिक्त भूमि में से 200 एकड़ भूमि भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना हेतु "इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर, एस्कार्ट फार्म एट काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर" सोसायटी को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (उत्तराखण्ड में यथा प्रभावी) की धारा 25 एवं वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है, उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायगी।

2- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत एस्कार्ट फार्म, काशीपुर जनपद ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) में भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) की स्थापना के संबंध में यथाशीघ्र अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा, शास्त्री भवन, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. निदेशक (प्रबन्धन), 430-सी विंग, शास्त्री भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
8. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग श्रीनगर।
9. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।